

संपादकीय ....

जन जोहार का तीसरा अंक आपके पास भेजने में थोड़ी देर हुई है. अगस्त माह का ऐतिहासिक संदर्भ है, 1945 में अमेरिकी साम्राज्यवाद द्वारा 6 और 9 अगस्त को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराकर मानवता के खिलाफ किया गया जघन्य अपराध, 8 अगस्त को कांग्रेस द्वारा दिया गया 'करो या मरो' का नारा, 9 अगस्त को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित 'विश्व आदिवासी दिवस' और 15 अगस्त को 'स्वाधीनता दिवस', सब अगस्त माह के साथ जुड़े हैं।

इस माह झारखंड में हमारी पार्टी और जनसंगठनों ने विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन में कम्युनिस्टों की भूमिका और उनके बलिदानों के इतिहास से आम लोगों को परिचित कराना और सांप्रदायिक ताकतों की नफरत की मुहिम के खिलाफ सद्भाव और एकता तथा संवैधानिक मूल्यों की हिफाजत के लिए नागरिकों के साझा मंच जैसे व्यापक प्लेटफार्म में सक्रिय भागीदारी मुख्य रही।

राज्य भर में हमारे आंदोलन एवं संगठन संबंधी गतिविधियों में उल्लेखनीय इजाफा हुआ। कोयला उद्योग में सीटू के नेतृत्व में विभिन्न स्तर पर लगातार आंदोलन जारी है. धनबाद जिले में कोल साइडिंग बंद कर 246 ठेका मजदूरों को बेरोजगार किए जाने के खिलाफ तीखा संघर्ष हुआ, साथियों को जेल जाना पड़ा, आंदोलन ने प्रबंधन को समझौते के लिए मजबूर किया, साथियों की रिहाई हुई. इस्पात उद्योग में भी बोकारो स्टील सिटी में प्रबंधन के मजदूर विरोधी रवैए के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी है। एच.ई.सी. में भी मजदूर लगातार आंदोलनरत हैं। सिंदरी में भी हर्ल प्रबंधन के खिलाफ मजदूर आंदोलन जारी है।

राज्य में सूखे की स्थिति पर किसान सभा ने प्रभावी हस्तक्षेप किया है. किसान सभा के आह्वान पर पूरे शेष पृष्ठ 3 पर .....

## साझी विरासत को आगे बढ़ाएँ - सुभाषिणी



हमारी साझी विरासत और अनेकता में एकता की गौरवशाली परंपरा है, जिसे आजादी के आंदोलन के दौर में यहां रहने वाले सभी धर्मों के अनुयायियों ने मिलजुलकर विकसित किया था. आज इसी विरासत पर भारी हमले हो रहे हैं और हमारे संविधान की प्रस्तावना और निर्देशिका को ही मिटाने की साजिश की जा रही है. यह बात आज रांची के एसडीसी सभागार में साझा मंच द्वारा आयोजित जन कंवेंशन में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए पूर्व सांसद, पोलित ब्यूरो सदस्य और आजाद हिंद फौज की रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की योद्धा कैप्टन लक्ष्मी सहगल की बेटी सुभाषिणी अली ने कही. उन्होंने कहा कि आज राजनीतिक फायदे के लिए धर्म का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हो रहा है. ऐसा करने वाली ताकतें

आज केंद्रीय सत्ता पर भी काबिज हैं वे वही ताकतें हैं जो आजादी के बाद जब देश का नया संविधान लागू हो रहा था उस समय उन्होंने भारत गणराज्य में समानता का अधिकार देने वाले संविधान के बजाय मनुस्मृति से निर्देशित संविधान लागू करने की वकालत की थी. शासन में आने के बाद यही ताकतें देश की जनता को समानता का अधिकार देने वाले भारत के संविधान को कमजोर करने का षडयंत्र कर रही हैं. आज देश की जनता बढ़ती हुई

महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है, दूसरी ओर एक व्यापक योजना के तहत देश की सार्वजनिक संपत्ति का मेगा सेल लगाकर देश की अर्थव्यवस्था और संप्रभुता को ही दांव पर लगाया जा रहा है साथ ही इस राष्ट्र विरोधी षडयंत्र से लोगों का ध्यान हटाने के लिए एक विशेष संप्रदाय के खिलाफ नफरत की मुहिम चलाकर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का संगठित अभियान चलाया जा रहा है. इस षडयंत्र का मुकाबला लोगों की साझी एकजुटता से ही किया जा सकता है. हमें खुशी है कि झारखंड में साझा मंच का गठन इस एकजुटता के लिए प्रयासरत है.

कंवेंशन का मुख्य प्रस्ताव फादर टोनी ने प्रस्तुत किया.

कंवेंशन को संबोधित करते हुए विनोबा भावे विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति डॉ. रमेश शरण ने कहा कि देश की आम जनता ने स्वतंत्रता संघर्ष के दौर में ही सांप्रदायिकता के झाड़ू-फूस को साफ कर एकता और सद्भाव की जो पगडंडी तैयार की थी उसे अवरूद्ध किए जाने की कोशिश की जा रही है. प्रख्यात फिल्मकार मेघनाद जी ने कहा कि हमारी परंपरा में ही धर्मनिरपेक्षता का रंग घुला हुआ है, इसे बेरंग करने की कोई भी साजिश सफल नहीं होगी.

कंवेंशन को संबोधित करते हुए विभिन्न

**1-3 सितंबर 2022**  
**राज्य भर में सघन कोष-संग्रह अभियान**  
कोडरमा राज्य कमिटी मीटिंग के निर्णय के आलोक में आगामी 1-3 सितंबर 2022 तक राज्य भर में हर स्तर पर सघन कोष संग्रह अभियान चलाया जाएगा जिसमें हर पार्टी सदस्य को अपनी भागीदारी सुनिश्चित करनी पड़ेगी।  
लगातार कोष संग्रह हर पार्टी सदस्य का राजनीतिक कर्तव्य है। कोष संग्रह अभियान द्वारा हम पार्टी शुभचिंतकों और पार्टी समर्थकों का हमारे जन संघर्ष में योगदान सुनिश्चित कराते हैं।

## विश्व आदिवासी दिवस और झारखंड

9 अगस्त 2022 को "विश्व आदिवासी दिवस था"। रांची में 9 अगस्त से ही दो दिवसीय "झारखंड जनजातीय महोत्सव" आरम्भ हुआ, जिसमें अनुसूचित जनजाति के विभिन्न पहलुओं और आयामों का प्रदर्शन हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 2022-2032 को "आदिवासी दशक" के रूप में घोषित किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य उनकी भाषा का संरक्षण और संवर्धन है। विश्व की जनसंख्या में 5% आदिवासी हैं। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में 8.6% और झारखंड में 26.2% आदिवासी हैं। झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजातियाँ हैं जिनमें 24 मुख्य जनजातियाँ और आठ आदिम जनजातियाँ हैं। आदिम जनजातियाँ मात्र 0.75% बची हैं।

विश्व के सबसे प्राचीन मानव समूह में शुमार, सबसे मेहनती, सबसे लोकतांत्रिक और प्रकृति के सह-अस्तित्व में रहने वाले आदिवासी इतने पिछड़े क्यों

गए? मानव विकास सूचकांक के करीब-करीब सारे ही पैमानों पर इनकी स्थिति आम भारतीयों से भी काफी खराब है। सीएनटी, एसपीटी, आरक्षण, वन संरक्षण कानून, पेसा, पाँचवीं अनुसूची जैसे कई कानूनों के बावजूद झारखंड के आदिवासियों की स्थिति में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। दरअसल इन कानूनों के माध्यम से उन्हें कुछ संरक्षण तो प्राप्त हुआ है लेकिन इनके व्यक्तिगत, सामूहिक, और सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सार्थक और सुनियोजित कार्रवाई का सर्वथा अभाव रहा है।

साक्षरता कष्ट और आशा के बीच का सेतु है और शिक्षा अभाव और विकास के बीच का पुल। झारखंड में 91% से ज्यादा अनुसूचित जाति के लोग ग्रामीण हैं, इसीलिए झारखंड के ग्रामीण इलाकों में स्कूल-कॉलेज की अत्यंत दयनीय स्थिति देखते हुए, इनके शिक्षा के स्तर और इनके

विकास को आसानी से समझा जा सकता है। वनोपज का उचित मूल्य ना मिलना, सिंचाई व्यवस्था की अनुपस्थिति में एक फसली खेती, और सूखे-ओलावृष्टि के चलते उसका भी नष्ट हो जाना, बड़ी संख्या में उनके प्रवासी बन जाने का मुख्य कारण है। विकास योजनाओं की आड़ में अपने जमीन से बेदखल हो कर बिना कोई विकल्प के विस्थापित होना भी इनकी नियति बन चुकी है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये आज सबसे शोषित नस्ल हैं।

धर्म-सत्ता-कॉरपोरेट के नापाक गठजोड़ की राजनीति का असर आदिवासियों पर भी व्यापक रूप से पड़ा है। आज विस्थापन, स्वामित्व, अस्तित्व आदि मुद्दों के ऊपर सरना कोड की प्राथमिकता है। दरअसल झारखंड में 32 अनुसूचित जनजातियों में से सिर्फ 4 का ही राजनीतिक वर्चस्व रहा है - संताल, शेष पेज 3 पर .....



# 38 सूत्री मांगों को लेकर एनसीओईए का धरना



एनसीओईए (सीटू) सीसीएल के बीएंडके क्षेत्रीय कमिटी द्वारा बीएंडके महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष करगली गेट स्थित गांधी चौक पर केंद्र सरकार एवं कोल इंडिया प्रबंधन की मजदूर विरोधी नीति के विरोध में 38 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया जिसकी अध्यक्षता क्षेत्रीय अध्यक्ष कामरेड

मनोज पासवान ने की। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से जेबीसीसीआई सदस्य सह महासचिव, एआईसीडब्ल्यूएफ, कॉ0 डीडी रामानंदन मौजूद रहे। मुख्य मांग के रूप में जेबीसीसीआई 11 का सम्मानजनक समझौता, मिनिमम गारंटी तीन प्रतिशत का विरोध, एनएमपी के तहत कोल इंडिया के 160 खदानों को निजी मालिकों के हवाले करने के विरोध में, सेवानिवृत्त कर्मियों को बिना आवास जमा किए ग्रेच्युटी का भुगतान करने की मांग आदि है। डीडी रामानंदन ने कहा कि सरकार कोयला उद्योग के निजीकरण करने के लिए कई तरह के रास्ते अपना रही है। सरकार ने

पहले कर्मशियल माइनिंग के तहत निजीकरण करना चाहा, जो सफल नहीं हुआ। अब नेशनल मोनिटाइजेशन पाइप लाइन के तहत कार्य करना चाहती है। कोयला मजदूर में वह ताकत है जो इसे रोक रहा है। उन्होंने कहा कि पिछले 15 से 20 वर्षों से इस निजीकरण को कोयला श्रमिकों ने विरोध कर रोक रखा है। अभी सरकार एक नया नियम निकालकर हर कंपनी का 25% शेयर बेचना चाह रही है। इस धरने में बड़ी संख्या में कोलियरी के मजदूर उपस्थित थे और इस अवसर कई मजदूरों ने यूनियन की सदस्यता ली। □

# अनाज-आटा पर जीएसटी के खिलाफ जुलूस



दिनांक 20 जुलाई को अखिल भारतीय किसान सभा एवं संयुक्त किसान मोर्चा के देशव्यापी अभियान के तहत झारखण्ड राज्य किसान सभा द्वारा भगत सिंह चौक, मुरी में जुलूस निकाल कर एमएसपी के लिए कानून, अनाज-आटा पर टैक्स, बेरोजगारी तथा अग्निपथ योजना के खिलाफ देशव्यापी अभियान के तहत कार्यक्रम किया गया। मुख्य वक्ता के रूप में झारखण्ड संयुक्त किसान मोर्चा के संयोजक सुफल महतो ने कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस अवसर पर सुखनाथ लोहरा, अमर महली, अरूण महतो, उमेश महतो सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। □

# सूखा क्षेत्र घोषित करने के लिए प्रदर्शन



कोडरमा



राहे



मेरगामा-गोड्डा



धनबाद



बहरागोड़ा



तोर्पा

# विज्ञान फिल्म फेस्टिवल



ज्ञान विज्ञान समिति झारखण्ड और ओबीआर ट्रेवल्स फिल्म के सहयोग से धनबाद जिले के सिंदरी में 2 दिवसीय विज्ञान फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 26 और 27 जुलाई 2022 को किया गया जिसमें "अगर वो देश बनाती", "चंदा के जूते", "बोल की लब आजाद है तेरे" आदि फिल्मों दिखाई गईं। □

# ठेका मजदूरों का प्रदर्शन



लंबित वेतन समझौता, पांच मजदूरों का माइन्स में किए गए ट्रांसफर के विरोध में और ठेका मजदूरों का सम्मान जनक समझौता के लिए आज सीटू, बोकारो द्वारा ईडी वर्क्स के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। □

**पाठकों से निवेदन.....**  
जन-जोहार का यह तीसरा अंक है। जन जोहार प्रकाशन टीम अपने पाठकों से बुलेटिन का स्वरूप और समाचार एवं विषय वस्तु पर प्रतिक्रिया और सुझाव की अपेक्षा करता है। आपका सुझाव बुलेटिन को और समृद्ध करेगा। □

# झारखण्ड पहुंचा एसएफआई का अखिल भारतीय जत्था



शिक्षा बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ अभियान के तहत भारत का छात्र फेडरेशन (एस एफ आइ) ने देश के पांच हिस्सों से जत्था निकाला है। पूर्वी क्षेत्र का जत्था बिहार से झारखण्ड में 17 अगस्त को पहुंचा। इस अवसर पर श्रमिक कल्याण चौक से एक बड़ी रैली निकाली गई जो झंडा चौक पहुंच कर सभा में बदल गया। सभा को

एसएफआई के अखिल भारतीय महासचिव मयूख विश्वास ने सम्बोधित करते हुए केंद्र की नई शिक्षा नीति के प्रावधानों की जम कर आलोचना की और उसे वापस लेने की मांग की।

महंगी होती शिक्षा और निजीकरण के कारण शिक्षा के आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाने की भी आलोचना की। जत्था का कोडरमा के विभिन्न शैक्षणिक कैंपसों में कार्यक्रम

आयोजित हुआ। 18 अगस्त को जत्था रांची पहुंचा जहां रांची में फादर कामिल बुल्के पथ स्थित सत्य भारती सभागार में इस जत्था का स्वागत किया गया। सभागार में एक कन्वेंशन भी आयोजित

किया गया जिसमें राजधानी के विभिन्न कालेजों के विद्यार्थी जिले भर से शामिल हुए। कन्वेंशन को एसएफआई के पूर्व राज्याध्यक्ष मो. स्टालिन के अलावा एसएफआई झारखण्ड के शुभ्रजीत सरकार, मोनाजीर खान और अमन कुमार ने सम्बोधित किया। □



## विश्व आदिवासी ...

..... शेष पेज 1 का

उराँव, मुंडा और हो। बाकी 28 जनजातियाँ और महिलाओं द्वाआधी आबादीका प्रतिनिधित्व नगण्य रहा है। ये आदिवासियों की लोकतांत्रिक पद्धति के विरुद्ध है और इनके पिछड़ने का एक प्रमुख कारण भी है।

इनकी राजनीतिक चेतना इतनी असमान है कि 48% आदिवासियों ने कभी मतदान ही नहीं किया है। पिछली लोकसभा में आदिवासी महिलाओं का प्रतिनिधित्व सिर्फ 1% था और इस लोकसभा में 2% है।

सैंकड़ों संगठनों में बिखरे हुए आदिवासी धर्म-सत्ता-कॉरपोरेट के आसान शिकार हैं। विपुल प्राकृतिक संसाधनों पर उनके सामाजिक हक पर कॉरपोरेट की वक्र दृष्टि है और सत्ता की मदद से आदिवासियों को धर्म के नाम पर उलझा कर उनको जमीन और उसके नीचे की अपार खनिज-सम्पदा से बेदखल करने की साजिश खुल कर चल रही है। इस साजिश के तहत ही आदिवासियों के हित में बने कानूनों को आदिवासियों के विरुद्ध ही बता कर उन्हें बदलने की कवायद जारी है। वन संरक्षण कानून, 1980 की नियमावली में

परिवर्तन कर ग्रामसभा के अधिकार को खत्म करना इसी की एक कड़ी है। आदिवासी संगठनों की इस पर चुप्पी चिंताजनक है।

सभी आदिवासियों को सारे विवाद और मतभेद अलग रख कर जल-जंगल-जमीन के स्वामित्व, आदिवासी अस्मिता और संविधान और संविधानिक प्रदत्त अधिकारों की रक्षा के लिए प्राथमिकता के आधार पर एकजुट हो कर संघर्ष करना होगा। यह सिर्फ आदिवासियों की लड़ाई ही नहीं है अपितु देश की एकता और सौहार्द के साथ संविधान पर हमले के खिलाफ देश के सभी देशभक्त लोकतांत्रिक नागरिकों की लड़ाई है।

आईए, हम सब मिलकर 9 अगस्त "अंग्रेजों भारत छोड़ो" के अस्सी साल बाद, उसी तर्ज पर "धर्म-सत्ता-कॉरपोरेट गठबंधन" गद्दी छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूँके। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) आदिवासियों के शोषण के खिलाफ लगातार कानून और आंदोलन के माध्यम से संघर्षरत रही है और सत्ता-कॉरपोरेट गठबंधन के नये हथकंडों से निपटने को तैयार है। □ - अमल पाण्डेय

## बीसीसीएल की तानाशाही-मजदूर जेल से नहीं डरते



लोदना में चले आंदोलन में सीपीआई(एम) के राज्य कमिटी नेता व बीसीकेयू के केंद्रीय सचिव सुरेश प्रसाद गुप्ता सहित 4 वामपंथी नेताओं को मजदूर आंदोलन को कमजोर करने के इरादे से झूठे मुकदमों में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। वास्तव में सीके साइडिंग में 246 मजदूरों को अचानक कार्य पर से हटा दिया गया, जिसके विरोध में बीसीकेयू लगातार आंदोलन कर रही है। इस आंदोलन से घबराकर ठेकेदार और पुलिस प्रशासन एवं बीसीसीएल प्रबंधन गठजोड़ नेताओं पर झूठा मुकदमा

दायर कर गैर संविधानिक तरीके से रात्रि के तीन बजे हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था।

आंदोलन के बाद कॉमरेड सुरेश प्रसाद गुप्ता सहित अन्य 4 वामपंथी नेता को माननीय अदालत द्वारा रिहा किया गया। रिहाई पर धनबाद मंडल कारा के समक्ष कार्यकर्ताओं का विशाल हुजूम जमा हुआ और कार्यकर्ताओं ने कॉमरेड सुरेश प्रसाद गुप्ता एवं अन्य सथियों को माला पहनाकर स्वागत किया एवं बीसीसीएल प्रबंधन विरोधी नारे लगाए और आंदोलन तेज करने का निर्णय लिया। □

## संपादकीय

..... शेष पेज 1 का

राज्य में प्रखंड मुख्यालयों में प्रदर्शन कर किसानों को राहत दिए जाने की मांग उठाई जा रही है। महिला मोर्चा के राज्य सम्मेलन के पूर्व प्रभाव वाले जिलों में सांगठनिक सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। छात्र मोर्चे पर 'शिक्षा बचाओ-देश बचाओ' नारे के अंतर्गत एस.एफ.आई द्वारा निकाले गए देशव्यापी जत्था का कोडरमा और रांची में कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें छात्रों की अच्छी भागीदारी हुई। युवा मोर्चे पर डीवाईएफआई द्वारा रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन का कार्यक्रम है।

केंद्र सरकार की तानाशाही और जन-विरोधी नीतियों के खिलाफ पार्टी द्वारा श्रृंखलाबद्ध आंदोलनों की व्यापक तैयारी है। राजनीतिक रूप से पार्टी ने स्थानीय मुद्दों के साथ बेरोजगारी और मूल्य वृद्धि को लेकर पूरे सितम्बर महीने में नीचे कमिटियों तक सघन अभियान चलाने का आह्वान किया है जो 20 सितंबर को अपने उत्कर्ष पर पहुंचेगा और राजधानी रांची में इन जनमुद्दों पर एक विशाल रैली होगी।

1 से 3 सितंबर तक पूरे राज्य में सभी पार्टी सदस्य आम जनता से पार्टी के लिए व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कोष संग्रह करेंगे।

मौजूदा चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने और झारखंड में एक जनपक्षीय राजनीतिक विकल्प देने के लिए पार्टी के सभी स्तर पर पार्टी, जनसंगठनों और पार्टी सिंपेथाइजर, सभी को आने वाले कार्यक्रमों में जुटना होगा। इसके लिये सदस्यों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है।

जय हिन्द □

## इस्पात मजदूरों का रोषपूर्ण प्रदर्शन



बोकारो, मजदूर विरोधी मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग को रद्द करने, जनवरी 2017 से एरियर का भुगतान करने, पदाधिकारियों के समान पर्व का एरियर देने, ग्रैज्युटी पर सिलिंग वापस लेने, 13% एम.जी. बी. के साथ 2 इन्क्रिमेंट देने, ठेका मजदूरों को सेल की न्यूनतम मजदूरी, ग्रैज्युटी, ग्रुप इश्योर्सेस और नाइट शिफ्ट भत्ता देने आदि मांगों के लिए सीटू के आह्वान पर इस्पात मजदूर मोर्चा (सीटू) द्वारा आज दिनांक 18 अगस्त को शाम 5 बजे एडमिन बिल्डिंग गेट के पास जुझारू प्रदर्शन किया गया। □

## नेतरहाट फायरिंग रेंज...

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा नेतरहाट फिल्ड फायरिंग रेंज को अवधि विस्तार नहीं दिए जाने की घोषणा का माकपा राज्य सचिवमंडल स्वागत करता है।

झारखंड सरकार का यह कदम संविधान की 5 वीं अनुसूची में उल्लेखित ग्राम सभा के अधिकारों को मजबूत करेगा क्योंकि लातेहार जिले के प्रभावित 39 राजस्व ग्रामों द्वारा आम सभा के माध्यम से इस फायरिंग रेंज को हटाए जाने की मांग की गई थी। इसके अलावा पिछले 30 वर्षों से इस इलाके की ग्रामीण जनता जिनमें बड़ी संख्या आदिवासियों की है, संगठित होकर आंदोलन कर रहे थे।

यह उनके लगातार संघर्षों का परिणाम है। माकपा शुरू से ही इस संघर्ष के साथ एकजुटता प्रदर्शित करती रही है। □

## ...जरूरी तो नहीं!

दिशाएँ गुंजायमान हैं 'जय श्रीराम' के जयघोष से, इसमें राम की 'जीत' हो.....जरूरी तो नहीं।

राष्ट्र, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद के इस उन्माद में, आम देशवासी की जीत हा.....जरूरी तो नहीं।

'कानून का राज' से 'कानून से राज' के सफर में, न्याय जीत ही जाए.....जरूरी तो नहीं।

जुमलों और लच्छेदार-लुभावने वादों-भाषणों से, 'अच्छे दिन' आ जाए.....जरूरी तो नहीं।

अशिक्षा, कुपोषण, बेकारी, गरीबी, महंगाई से, हम 'विश्व गुरु' बन जाए.....जरूरी तो नहीं।

हिंदू राष्ट्र की चाशनी में, नफरती मुहिम चलाने से, हम बंट के बिखर जाए.....जरूरी तो नहीं।

मजदूर-किसानों पर हमले, ये कानून बदलने से, वो मैदान से हट जाए.....जरूरी तो नहीं।

5 किलो अनाज, 500 रुपये में जब सिमटे हैं हम, तुम्हें वोट कर जाए.....जरूरी तो नहीं।

माना कि दमन तेरा हमको रुला रहा है 'अमल', हम आवाज ना उठाएँ.....जरूरी तो नहीं।

## प्लांट गेट पर प्रदर्शन

स्टील वर्क्स फैडरेशन ऑफ इंडिया के आह्वान पर बोकारो स्टील के चार मजदूरों के सरपेंशन और एक मजदूर का जबरदस्ती भद्रावती ट्रांसफर को बिना शर्त वापस लेने एवं सम्मानजनक वेतन समझौता एवं ठेका मजदूरों की मांगों को लेकर 11 जुलाई की शाम 5 बजे बोकारो स्टील प्लांट के मेन गेट पास सेक्शन के पास युनियन द्वारा जुझारू प्रदर्शन किया गया। □

## साइंस फोरम का नेत्र शिविर

झारखंड साइंस फोरम ने 21.08.2022 को डिबडीह बस्ती रांची में निशुल्क नेत्र जांच एवं स्वैच्छिक रक्त दान शिविर का आयोजन किया। मौके पर वार्ड पार्षद सबिता कुजुर भी मौजूद थी। झारखंड साइंस फोरम की ओर से सचिव सुभाष चटर्जी, कोषाध्यक्ष किशोर चक्रवर्ती, सुकेशी कर्मकार, रवि कुमार, सुब्रत भट्टाचार्य, सुजोय बनर्जी, गोलाप मोहम्मद चौधरी, अनिमेष शरण, तुषार शीट, विवेक राय आदि उपस्थित थे। □

## साझा मंच .....

..... शेष पृष्ठ 1 का

धार्मिक समूहों के प्रतिनिधि, जिसमें केंद्रीय गुरुद्वारा सिंहसभा की परमजीत कौर, इस्लाम धर्म की ओर से मौलाना, ईसाई धर्म की ओर से फादर एलेक्स एक्का, बुद्ध सोसायटी की ओर से तथागत जैनेन्द्र कुमार ने अपने वक्तव्य में कहा कि सभी धर्मों का मूल बुनियाद शेष पेज 3 पर.... दया, सदभाव, करुणा, भाईचारा आदि है। इस बुनियाद को मजबूत करके ही हमारी साझी विरासत के मूल्यों की रक्षा की जा सकती है।

कवेंशन को किसान सभा के के. डी. सिंह और सोशल एक्टिविस्ट किरण जी ने भी सम्बोधित किया।

कवेंशन के आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा अमल पांडे ने रखी।

## स्वांग वाशरी में वार्ता

सीसीएल स्वांग वाशरी प्रबंधन के साथ एनसीओईए (सीटू) का 13 सूत्री मांग



पत्र पर 11 जुलाई 2022 को वार्ता हुई जिसमें एनसीओईए (सीटू) के केंद्रीय उपाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर एवं कथारा क्षेत्रिय सचिव सह सीसीएल वेलफेयर बोर्ड सदस्य प्रदीप कुमार विश्वास और प्रबंधन की ओर से परियोजना पदाधिकारी विजय कुमार एवं पर्सनल मैनेजर रत्नाकर उपस्थित थे। □

## स्वतंत्रता संग्राम में कम्युनिस्टों का गौरवमयी इतिहास – बृन्दा करात



भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कम्युनिस्टों ने बड़ी कृबानियाँ दी हैं। 'पूर्ण स्वराज' के प्रस्ताव को पास कराने से लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लगभग सारे क्रांतिकारी गतिविधियों में कम्युनिस्ट हमेशा आगे रहे हैं और शहादत दी है। "भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का गौरवशाली इतिहास और वर्तमान चुनौतियाँ" विषय पर झुमरीतिलैया में आयोजित सेमिनार में मुख्य वक्ता के रूप में बोलते हुए पूर्व सांसद और पोलितब्यूरो सदस्य बृन्दा करात ने कहा कि आज हर घर तिरंगा के नाम पर राशन की दुकानों से तिरंगे का व्यापार करवाने वालों से सावधान रहने की ज़रूरत है। सेमिनार को संबोधित करते हुए पोलित ब्यूरो सदस्य डॉ॰ रामचंद्र डोम ने स्वतंत्रता संग्राम और संविधान पर आज के शासकों की भूमिका की पोल खोली। सेमिनार को राज्य सचिव प्रकाश विप्लव ने भी संबोधित किया। □

## बर्मिंघम कॉमन वेल्थ गेम्स में झारखण्ड का जलवा

8 अगस्त को संपन्न हुए बर्मिंघम कॉमन वेल्थ गेम्स में झारखण्ड का भी प्रदर्शन बेहतरीन रहा. यहां से लॉन बॉल्स में महिला टीम में लवली, रूपा रानी, और पुरुष टीम में दिनेश, चंदन और सुनील बहादुर ने चुनौती दी। महिला टीम ने पहली बार आस्ट्रेलिया



और दक्षिण अफ्रीका जैसी सशक्त टीमों को हरा कर गोल्ड जीता। पुरुष टीम ने रजत जीता। झारखण्ड की ओर से भारतीय महिला हॉकी टीम में खेल रही निक्की प्रधान, सलीमा टेटे व संगीता ने कांस्य पदक जीता। सभी पदक विजेताओं को हार्दिक बधाई। □



धनबाद

## तस्वीरों में झंडोत्तोलन ...



झारखण्ड राज्य कमिटी, रांची



बोड़ाम



बोकारो स्टील सिटी



पाकुड़



रोड़ाबांध



सिन्दरी



कोडरमा



साझा मंच, झारखण्ड



राहे, रांची



## पार्टी कोष में सहयोग की अपील

संघर्ष कोष के लिये स्वेच्छा से निम्नलिखित बैंक खाते में अपना योगदान करें।

**Communist Party of India Marxist**  
**Bank : Bank of Baroda**  
**Main Branch, Ranchi**  
**A/c No. : 00170200000219**  
**IFSC Code : BARB0RANCHI**